बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों का व्यापक विश्लेषण और सुझाव

Jyotsna Singh

Babu jagjivan Ram institute of law, Bundelkhand University,Jhansi

अंशग्रंथः

यह अंशग्रंथ एक गहरे अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साइबर–सक्षम अपराधों और पोक्सो अधिनियम के संघर्षपूर्ण संगम का विश्लेषण किया गया है। समाज में एक विचारशील और सृजनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए यह अंशग्रंथ विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास करता है, ।

इसमें साइबर–सक्षम अपराधों के विभिन्न प्रकारों की परिभाषा और वर्गीकरण किया गया है। पोक्सो अधिनियम की परिचय और इसके उद्देश्यों का विवेचन किया गया है। यह अंशग्रंथ विद्यमान कानूनी अंशों की पर्याप्तता की जांच करता है और उनके प्रवाद में कोई कमी और चुनौतियों को उजागर करता है।

इसके अलावा, कानूनी रूप से, आपत्ति निवारण, और जागरूकता अभियानों की मौजूदगी का मूल्यांकन करते हुए, यह विचार करता है कि बच्चों के साथ साइबर–सक्षम अपराधों के खिलाफ योजनाएँ कैसे बढ़ाई जा सकती हैं।

अंत में, इस अंशग्रंथ ने कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से, मानविकी दृष्टिकोण से और सामाजिक कार्य में संबोधन करने के लिए सुझाव प्रदान किए हैं, जिससे इस गंभीर समस्या का समाधान किया जा सकता है।

परिचय

कंप्यूटर के आविष्कार ने जीवन को इतना आसान बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था; इसका उपयोग दुनिया भर में व्यक्तिगत से लेकर बड़े संगठनों तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। आजकल इंटरनेट दुनिया भर में लोगों की आधुनिक जीवनशैली का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। यह एक साथ सशक्त, आकर्षक, कठिन और भयानक है। अधिकांश लोगों के लिए इंटरनेट रहस्यमय, वर्जित, समझ से बाहर और भयावह बना हुआ है। दशकों से, अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर रहे हैं, या तो अपने लाभ के लिए या दूसरों के लाभ के लिए। इसने साइबर अपराध को जन्म दिया।

महिलाएं और बच्चे समाज के सबसे कमजोर सदस्यों में से हैं, जिससे वे साइबर अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। यह महामारी के दौरान विशेष रूप से सच था, भले ही पुरुष

और वयस्क भी कई साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशील थे। इंटरनेट के इस उपहार का उपयोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग गलत काम करने के लिए करते हैं और फिर इंटरनेट द्वारा दी गई आड़ में खुद को छुपा लेते हैं। साइबर दुनिया अपने आप में एक आभासी वास्तविकता है जहां कोई भी अपनी पहचान छुपा सकता है या गढ़ सकता है।

महामारी के दौरान दुनिया भर में हर किसी को कठिन समय का सामना करना पड़ा है। कोविड–19 वायरस को एक ऐसी आपदा के रूप में दिखाया गया है जिसने कई लोगों की जान ले ली है और लाखों अन्य लोगों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित होना पड़ा है। महामारी के परिणामस्वरूप लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन साइबर अपराधों का सबसे संवेदनशील और सीधा लक्ष्य बच्चे हैं, खासकर वे जिन्हें या तो छोड़ दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने माता–पिता दोनों को खो दिया है या जो अस्थायी रूप से उनसे अलग हो गए हैं क्योंकि उनमें से एक को बीमारी हो गई है। आज के समाज में बच्चे सबसे कमजोर वर्ग हैं और उनके बहुमत स्तर की कमी के परिणामस्वरूप, साइबर दुनिया में उनका आसानी से शोषण किया जाता है। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों का यौन शोषण भी ऑनलाइन होने लगा है। साइबर अपराध दिन–ब–दिन बढ़ रहा है और व्यक्तियों का एक बड़ा समूह हैकिंग, चोरी, साइबर स्टॉकिंग, धोखाधड़ी, दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर, बच्चों की याचना आदि का शिकार बन गया है। इस व्यवहार के दो मुख्य रूप हैं। पहले में ट्रैफ़िक और/या बाल पोर्नोग्राफ़ी एकत्र करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना शामिल है। दूसरे में व्यापक रूप से प्रचारित समस्या शामिल है वयस्क पुरुषों के बच्चे ऑनलाइन नाबालिगों से सेक्स की मांग करते हैंश। जब बच्चे अपने माता–पिता से अलग हो जाते हैं या उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, तो वे अधिक असुरक्षित होते हैं। बच्चे आसानी से अनैतिक व्यवहार में शामिल हो जाते हैं और खुद को साइबर अपराधियों का आसान शिकार बना लेते हैं क्योंकि उनके पास यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं होता है कि कोई विशिष्ट वेबसाइट देखने के लिए स्वीकार्य है या नहीं, साथ ही साथ यह भी कि कोई विशेष छवि या वीडियो डाउनलोड किया जाना चाहिए या नहीं। इस वजह से, यौन शिकारियों और अन्य साइबर अपराधियों के लिए इन बच्चों के गैजेट तक पहुंचना और उनमें हेरफेर करना काफी आसान है।

दुनिया भर में अधिक से अधिक लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के कारण साइबर अपराध बढ़ रहा है। अनुमान है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप लोगों और व्यवसायों को 100 बिलियन से अधिक धनराशि का नुकसान हुआ है। दुनिया भर में, पिछले दशकों में विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वृद्ध वयस्क इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक तेजी से बढ़ता हुआ समूह है। बाकी आबादी की तरह, इंटरनेट प्रौद्योगिकी की बढ़ती स्वीकार्यता ने वृद्ध वयस्कों को ऑनलाइन

अपराध के खतरों से अवगत कराया है। हालाँकि धोखाधड़ी सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, वृद्ध वयस्क असुरक्षित रूप से असुरक्षित होते हैं। प्रौद्योगिकी, सापेक्ष धन के साथ परिचितता की कथित कमी और शर्म की भावनाओं के कारण अधिकारियों को अपराध की रिपोर्ट करने में झिझक के कारण वृद्ध लोग अपराधियों के लिए आकर्षक लक्ष्य पाए गए।

साहित्य की समीक्षा

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध, अदिति श्रीवास्तव, 2021

इस लेख में लेखक ने बताया कि इंटरनेट उपयोग की दर बढ़ने के साथ, भारत में लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराध की दर अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई। 2020 में महिलाओं के खिलाफ कुल 704 और 2021 में (जुलाई तक) 504 साइबर अपराध दर्ज किए गए। साइबरस्टॉकिंग, सेक्सटॉर्शन, साइबर–हैकिंग, साइबर–बुलिंग, यौन शोषण (पीड़ित के खिलाफ अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के उपयोग सहित), साइबरसेक्स ट्रैफिकिंग और फ़िशिंग महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक बार होने वाले साइबर अपराध हैं। साइबरबुलिंग, बच्चों को संवारना, साइबरसेक्स तस्करी और नाबालिगों का यौन शोषण महामारी के दौरान बच्चों के खिलाफ किए गए सबसे प्रचलित साइबर अपराधों में से हैं। अपनी असुरक्षा के कारण, महिलाएं और बच्चे लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराधियों और यौन शिकारियों के लिए विशेष रूप से आसान शिकार थे।

बच्चों के विरुद्ध इंटरनेट अपराध, कीथ एफ डर्किन, 2012

बच्चों के विरुद्ध इंटरनेट अपराध एक समकालीन सामाजिक समस्या है जिसने माता–पिता, शिक्षकों, विधायकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों का बहुत ध्यान आकर्षित किया है। इस घटना की कई मीडिया रिपोर्टों के साथ इस घटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इन अपराधों में बाल पोर्नोग्राफी अपराध, साथ ही वयस्कों द्वारा नाबालिगों को यौन उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन आग्रह करना शामिल है। हाल के राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आंकड़ों के आधार पर, अपराधों, अपराधियों और पीड़ितों की विशेषताओं की जांच की जाती है। बच्चों के विरुद्ध इंटरनेट अपराध करने वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन और वर्गीकरण से संबंधित कई मुद्दों का भी पता लगाया गया है। इस व्यवहार की रोकथाम और ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा करने वाले कानूनों को लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा की जाती है।

पी.के. वनिता, (2012) ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों का पता लगाने, रोकथाम और जांच के लिए साइबर अपराधों के पहले स्तर और दूसरे स्तर के तकनीकी ज्ञान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये मुद्दे भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच, अभियोजन और दंड से संबंधित हैं।

वीरेंद्र कुमार, (2018) ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों पर चर्चा की है। लेखक ने बताया है कि, इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं में वृद्धि से साइबर अपराध दर में वृद्धि हुई है। लेखक की राय है कि पीड़ित महिलाओं को आगे आना चाहिए और अपराध के खिलाफ विशेष साइबर अपराध विरोधी सेल में रिपोर्ट करनी चाहिए। लेखिका की राय में साइबर अपराधों के प्रति महिलाओं में जागरूकता और इंटरनेट, सोशल मीडिया के उपयोग से निश्चित रूप से साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और साइबर अपराधों में कमी आएगी।

एन अग्रवाल, (2014) ने साइबर अपराधों पर चर्चा की है और भारत में महिलाओं के खिलाफ सुरक्षा कमजोरियों को रेखांकित किया है। अध्ययन के माध्यम से लेखिका ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में पुलिस अधिकारियों, परामर्शदाता साइबर सेल अधिकारियों आदि की राय/धारणाओं को भी समझा है। लेखक ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की भी चर्चा की है।

बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध

- बच्चे और किशोर आसानी से बॉक्स में शामिल होने के लिए अगला आसान लक्ष्य हैं। यहां बच्चों के विरुद्ध साइबर–अपराधों के कुछ सामान्य रूपों का वर्णन किया गया है, वे हैं;
- बच्चों का यौन शोषण इसमें बाल यौन शोषण सामग्री जैसे बच्चों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो, फोन कॉल/वीडियो कॉल पर बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण शामिल है, जहां बच्चों को यौन कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- बच्चों के लिए अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट सामग्री शिक्षा और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करते समय या सोशल मीडिया पेज के माध्यम से जाते समय, बच्चों को कुछ वेबसाइटें खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जो उन्हें स्पष्ट यौन सामग्री और अश्लील वीडियो/छवियों की ओर निर्देशित करती हैं। इससे बच्चे की मानसिकता तो भ्रष्ट होती है लेकिन अपराधी को व्यूज और पैसा मिलता है।
- साइबरसेक्स तस्करी यौन तस्करी के विपरीत, पीड़ित दुर्व्यवहार करने वाले के सीधे संपर्क में नहीं आता है। साइबरसेक्स तस्करी में, डीलर एक केंद्रीय स्थान से यौन/अंतरंग कृत्यों को प्रदर्शित करते हुए पीड़ित की फिल्मों, या तस्वीरों को लाइव–स्ट्रीम करता है और सामग्री को यौन शिकारियों और खरीदारों को ऑनलाइन बेचता है। अपराधी बच्चों को हेरफेर और जबरदस्ती के माध्यम से साइबरसेक्स तस्करी का हिस्सा बनाकर उनका यौन शोषण कर रहे हैं।

- साइबरबुलिंग इसमें पीड़ित बच्चे के खिलाफ कठोर, मतलबी, अपमानजनक या क्रूर टिप्पणियाँ और संदेश शामिल हैं। बच्चों को उनके मासूम स्वभाव के कारण धमकाना आसान होता है और अपराधियों के लिए आभासी प्लेटफार्मों पर बच्चों को धमकाना और भी आसान हो जाता है। साइबरबुलिंग के कारण; वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से स्कूल की कक्षाओं से बचना, अचानक इंटरनेट और कंप्यूटर उपकरणों का उपयोग बंद करना चाहते हैं, अपने डिजिटल जीवन, संकट और बच्चों के बीच भावनात्मक अस्थिरता के बारे में गुप्त रहना।
- बच्चे को संवारना अपराधी बच्चे के यौन शोषण के उद्देश्य से पीड़ित बच्चे के साथ एक भावनात्मक और विश्वासपूर्ण बंधन बनाकर उससे दोस्ती करता है। बच्चे आसानी से भरोसा कर लेते हैं और इसलिए, अपराधियों के लिए उनके साथ ऐसा बंधन बनाना बहुत आसान हो जाता है। एक बार बंधन बन जाने के बाद, अपराधी यौन कृत्य करने के लिए बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों की देखभाल करना महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रतिबद्ध साइबर अपराधों में से एक रहा है। बाल संवारने वाले ऑनलाइन संचालन करने और बच्चों का विश्वास हासिल करने में सक्षम थे और इंटरनेट की दुनिया के अंधेरे पक्ष के बारे में बच्चों और माता–पिता की अनभिज्ञता के कारण उनके लिए ऐसा करना आसान हो गया।

बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध तथा पोक्सों अधिनियम

बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध एक गंभीर और बढ़ती चिंता है, और दुनिया भर के विभिन्न कानूनों का उद्देश्य ऐसे अपराधों को संबोधित करना और रोकना है। भारत में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सों अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है जिसे विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें डिजिटल माध्यमों से किए गए अपराध भी शामिल हैं।

2012 में अधिनियमित पोक्सों अधिनियम, बच्चों के यौन शोषण और शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित और वर्गीकृत करता है। यह बाल दुर्व्यवहार पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को पहचानता है और इसमें बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

यहां बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध और पोक्सों अधिनियम से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैंरू

यौन अपराधों की परिभाषाः पोक्सों अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें ऑनलाइन ग्रूमिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी और ऑनलाइन शोषण के अन्य प्रकार जैसे डिजिटल माध्यमों से किए गए अपराध शामिल हैं।

ऑनलाइन ग्रूमिंगः अधिनियम ऑनलाइन ग्रूमिंग के संभावित खतरे को पहचानता है, जहां अपराधी बच्चों का यौन शोषण करने के इरादे से इंटरनेट पर उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसमें यौन शोषण के लिए किसी बच्चे का विश्वास हासिल करने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे दोस्ती करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

बाल पोर्नोग्राफ़ीः बाल पोर्नोग्राफ़ी के निर्माण, वितरण और उपभोग को अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है। इसमें किसी बच्चे से जुड़े स्पष्ट यौन आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण शामिल है।

सज़ाः अधिनियम में बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कारावास और जुर्माना सहित कठोर दंड का प्रावधान है। सज़ा की गंभीरता अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती है।

विशेष अदालतेंः अधिनियम बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का आदेश देता है। इन अदालतों को बच्चों के प्रति अधिक अनुकूल और पीड़ितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रिपोर्टिंग और सहायताः अधिनियम अपराधों की रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर देता है और कानूनी कार्यवाही के दौरान बच्चे की सहायता के लिए विशेष शिक्षकों या विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

डिजिटल साक्ष्यः अधिनियम अपराधों पर मुकदमा चलाने में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका को मान्यता देता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दृश्य–श्रव्य सामग्री और डिजिटल रूप में कोई अन्य सामग्री शामिल है।

बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है। बच्चों, अभिभावकों और देखभाल करने वालों को ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को समझने और उचित सावधानी बरतने में मदद करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों को ऑनलाइन बाल शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देने के लिए अक्सर रिपोर्टिंग तंत्र और हेल्पलाइन स्थापित की जाती हैं।

निष्कर्ष

बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध का मुद्दा एक गंभीर चिंता का विषय है जिसके लिए नाबालिगों की भलाई की सुरक्षा के लिए व्यापक कानूनी ढांचे और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, यौन दुर्व्यवहार और शोषण के विभिन्न रूपों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सुविधा भी शामिल है।

अधिनियम न केवल अपराधों को परिभाषित और वर्गीकृत करता है बल्कि प्रौद्योगिकी की विकसित प्रकृति और बच्चों के खिलाफ अपराधों में इसकी भूमिका को भी पहचानता है। ऑनलाइन ग्रूमिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी और डिजिटल शोषण के अन्य रूपों से संबंधित प्रावधान डिजिटल युग द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के लिए कानूनी ढांचे को अपनाने के महत्व को रेखांकित करते हैं।

विशेष अदालतों की स्थापना, त्वरित सुनवाई पर जोर और कानूनी कार्यवाही में डिजिटल साक्ष्य को शामिल करना बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, अधिनियम युवा पीड़ितों की अनूठी जरूरतों को पहचानते हुए, कानूनी प्रक्रिया में बच्चों के अनुकूल और संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

रोकथाम बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने का एक प्रमुख पहलू है, और शिक्षा और जागरूकता पहल बच्चों, माता–पिता और शिक्षकों को डिजिटल परिदृश्य में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, कानून प्रवर्तन, समुदायों और सहायता सेवाओं के बीच सहयोग आवश्यक है।

उभरती तकनीकी चुनौतियों के सामने, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ कानूनी ढांचे को अद्यतन और अनुकूलित करने के चल रहे प्रयास आवश्यक हैं। बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन स्थान बनाना एक साझा जिम्मेदारी है, जहां वे बिना किसी नुकसान के खोज और सीख सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Section 43-75, Infotmatin and Technology (Amendment) Act, 2008

2. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

3. Gautam, R., “Proliferation of Cyber Crime and Indian legal system with special reference to Gwalior Division” Available at: https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/250817 Retrieved on: 22/07/2021

4. Gautam, Ritu, Cyber crime in India, Available at: http://hdl.handle.net/10603/250817